मजदूरों का अपना कोई देश नहीं होता ।

दुनियां के मजदूरो, एक हो !

फरीदाबाद मजदूर समाचार

मजदूरों की मुक्ति खुद मजदूरों का काम है ।

दुनियां को बदलने के लिए मजदूरों को खुद को बदलना होगा ।

RN 42233 पोस्टल रजिस्ट्रेशन L/HR/FBD/73

नई सीरीज नम्बर 28 | अक्टूबर 1990 | 50 पैसे

वर्तमान उथल—पुथल और मजदूर

भारत में इस समय मची धमा—चौकड़ी पर गौर करने के लिये आइये हम पहले अपने दिसम्बर 89 अंक के लेख "नाटक से नौटंकी" के कुछ अंशों पर फिर एक नजर दौड़ायें — "···लम्बे समय से भारत में चल रहा पूंजीवादी चुनाव और ससदवाद का नाटक अब नौटंकी की स्थिति में पहुँच गया है । इसलिये लगता है कि पूंजीवादी चुनाव और ससदवाद का भ्रमजाल शीघ्र ही यहाँ एक बार तार-तार होने वाला है । लगता है कि दुनियाँ में चल रही पूंजीवादी जनतन्त्र की लहर के उलट भारत में पूंजीवादी तत्व शीघ्र हो नगे दमन की राह पकड़ेंगे । यहाँ चुनाव के तत्काल बाद इस समय मचे "जनतन्त्र" के शोर में भी हम यह इसलिए कह रहे है क्योंकि वस्तुगत हालात इस किस्म की बन गई हैं । उदारवादी पूंजीवादी कितना ही हो-हल्ला क्यों न मचायें, सख्ती-सख्ती-सख्ती की मांग शीघ्र ही पूंजीवादी शोर की शक्ल ग्रहण करेगी । पूंजीवादी चुनाव और संसदवाद को बोरी में बन्द करना यहां पूंजी की जरूरत बन गया है । और क्रान्तिकारी मजदूर आन्दोलन आज यहां कमजोर है इसलिये कुछ समय तक भारत में सामाजिक जीवन में पहल कदमी पूंजी के नुमाइन्दों के हाथों में रहती लगती है । इन हालात में साल—दो साल में कौन सा फौजी जनरल या हिन्दुवादी हिटलर यह काम हाथ में लेगा यह हम अभी नहीं कह सकते । पर हां, पूंजीवादी चुनाव और ससदवाद को यहां नाटक से नौटंकी बनने, इस पूंजीवादी भ्रमजाल के झीने पड़ने का यह परिणाम निकलता नजर आता है । ·····

"और पूंजीवादी नाटक के नौटकी बनने के इस दौर के आरम्भ में नेता रूपी पूंजी के नुमाइन्दे आमतौर पर दमन से बचने की कोशिश करेंगे । नेता लोग "लोकप्रिय" होने की भागमभाग में शामिल होंगे । ······"

दस महीनों से हम कश्मीर हो चाहे पजाब, हिमाचल हो हरियाणा हो या फिर मध्य प्रदेश, सामाजिक असन्तोष से निपटने के लिये हर जगह फौज का अधिकाधिक इस्तेमाल देख रहे हैं । यह घटनाक्रम का एक पहलू है । दूसरा पहलू है नेताओं की "लोकप्रिय" होने की होड़ — कोई देहात और शहर का शोर मचा रहा है तो कोई जातिगत आरक्षण का, कोई रथ यात्रा पर निकल पड़ा है तो कोई सद्भावना के मन्त्र जप रहा है, और गोष्ठियों की तो भरमार हैं इन दिनों······ "लोकप्रिय" होने की नेताओं की होड़ ने पुलिस व नागरिक प्रशासन तन्त्र को पगु बना दिया है । प्रशासन के छुट-पुट मामले भी इन हालात में विस्फोटक रूप ग्रहण कर फौज के हस्तक्षेप की मांग करने लगे हैं । पूंजीवादी ससदीय ढांचा इस समय यहां पूंजीवादी व्यवस्था के सचालन में नाकारा सिद्ध हो रहा है और पूंजी के तेज-तर्रार नुमाइन्दे अब यह महसूस करने लग गए लगते हैं । हिन्दुवादी हिटलर या फौजी जनरल में से किसे सख्ती लागू करने की कमान सौंपी जाये यह अभी वे तय नहीं कर पाये लगते हैं । पर स्थिति तेजी से बदल रही है । इसलिए साल-दो साल में ही आरम्भ होते दिखते नगे दमन के दौर से निपटने के लिये मजदूर आन्दोलन को अभी से कदम उठाने चाहियें ।

पूंजीवादी संसदवाद के नाटक से नौटंकी की स्थिति में पहुँचने को भारत की वस्तुगत विशेषता के सन्दर्भ में देखना आने वाले दिनों की तैयारी के लिए जरूरी है । दसियों करोड़ कगाल किसान व दस्तकार, दिवालिएपन की कगार पर खड़े करोड़ों टट्पूंजिए, लम्पटों की एक बड़ी व बढ़ती तादाद और इस सबके साथ करोड़ों मजदूर जिनमें औद्योगिक मजदूरों का वजनदार स्थान है— यह है विश्व पूंजी की इस कमजोर इकाई, भारत की वस्तुगत स्थिति । अपनी कमजोरी की वजह से यह पूंजी इकाई अपने बोझे को अन्य पूंजी इकाइयों पर थोपने में अधिक समर्थ नहीं है । इसलिए करोड़ों किसानों—दस्तकारों—टट्पूंजियों-लम्पटों का बदहवास गुस्सा तथा शोषण के प्रतिरोध में उठते मजदूरों के कदम हर समय भारत में अति—विस्फोटक वस्तुगत स्थिति का निर्माण करते हैं । इसीलिये अब तक वाला भारतीय पूंजीवादी जनतन्त्र भी यूरोपीय नजरों से देखने पर एकतन्त्रीय दमन नजर आता रहा है । और अब यहाँ पूंजीवाद के संचालन के लिए नगा दमन आवश्यक बन गया है ···· ईरान, बर्मा, लंका, लेबनान, चीन, कम्बोडिया, अफरीकी और दक्षिण अमरीकी देशों से भी भयंकर हिंसा, मार-काट और दमन—शोषण का आगमन यहां होने को ही है । क्रान्तिकारी मजदूर आन्दोलन इस समय अपनी अति कमजोर स्थिति की वजह से दमन की इस काली रात के आगमन को रोकने में तो सक्षम नहीं है पर यह अच्छी तरह समझने की जरूरत है कि क्रान्तिकारी मजदूर आन्दोलन का विकास ही दमन की काली रात को कम से कम समय तक कायम रहने देगा ।

क्रान्तिकारी मजदूर आन्दोलन को विश्व परिप्रेक्ष में ही समझा जा सकता है तथा इसकी समस्याओं के समाधान ढूंढे जा सकते हैं । इसलिए आइये दुनिया के पैमाने पर हालात पर एक नजर डालें ।

पूंजीवादी व्यवस्था का गहराता संकट और उससे लाजिमी तौर पर जुड़ा सामाजिक असन्तोष पिछले साठ—सत्तर साल में क्रान्तिकारी राह पर बढ़ने की बजाय विरासत में मिली बेड़ियों के इर्द-गिर्द लोगों को जुटा कर इन सामाजिक बेड़ियों को मजबूत करता रहा है । दुनिया के हर हिस्से में बढ़ता असन्तोष इस दौर में स्वयं को आमतौर पर देश-धर्म-नस्ल-भाषा भेद जसी पूंजीवादी व पूर्व-पूंजीवादी अन्धी गलियों में अभिव्यक्त करता है । भौतिक हालात द्वारा देशों तक की दीवारें तोड़ कर विश्व मानव समुदाय के गठन को सम्भव व आवश्यक बना दिये जाने की स्थिति में मानवों के परस्पर विरोधी टुकड़ों में बंटते जाने की प्रवृति को पलटने के लिए इसे समझना जरूरी है । आइये कोशिश करें ।

इस सदी के आरम्भ के साथ पूंजीवाद की पतनशील अवस्था आरम्भ हुई । इस अवस्था के प्रथम बड़े संकट ने 1914 में पहले पूंजीवादी विश्व युद्ध को जन्म दिया । पूंजीवादी विनाश के खिलाफ 1917 में रूस-जर्मनी—आस्ट्रिया-हंगेरी-इटली-इंग्लैंड को अपनी लपेट में लेती यूरोप पैमाने की क्रान्तिकारी मजदूर लहर उठी । विभिन्न ऊंचाइयों को छूती वह लहर रूस में अपने शिखर पर पहुँची । दमन-शोषण के सर्वोच्च सगठन, राज्य मशीनरी और उसके स्तम्भों, पुलिस-फौज को क्रान्तिकारी मजदूर लहर ने रूस में अक्टूबर 1917 में तहस—नहस कर दिया । आम मजदूर हथियार बन्द हुये और मजदूर परिषदों—सोवियतों के हाथों में सत्ता के साथ रूस में मजदूर पैरिस कम्यून की राह पर आगे बढ़े । पर शीघ्र ही क्रान्ति के गर्भ से ही प्रतिक्रान्ति उभरी और 1918 में ही एक नई पुलिस-फौजवाली राज्य मशीनरी के निर्माण के लिए तेजी से कदम उठाये गए । आम मजदूरों को निहत्था किया गया । मजदूर परिषदें-सोवियतें नाम भर को रह गई और सत्ता तेजी से शक्तिशाली हो रही नई फौजी-नौकरशाही मशीनरी के सचालनों के हाथों में केन्द्रित हो गई । रूस और फिर चीन-पोलैंड आदि में दमन-शोषण की संचालक फौजी-नौकरशाही मशीनरी को समाजवाद का लेबल चिपका दिया गया । साठ-सत्तर साल से मजदूरों के अति क्रूर दमन-शोषण को मजदूरों का राज कहा जाता रहा है ।

खैर ! मूल बात यह है कि दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय के पतन की तरह ही एक बार फिर क्रान्ति के गर्भ से प्रतिक्रान्ति उभरी । हमारे विचार से इस घटनाक्रम का बुनियादी कारण यह है कि उन्नीसवीं सदी के अन्तिम दौर में पूंजीवाद में जो परिवर्तन आये उनका विश्लेषण करने में मार्क्सवाद का विद्यमान स्तर पर्याप्त नहीं था । और, मार्क्सवाद के विकास का काम हाथ में लेने की बजाय उस दौर के अधिकतर मार्क्सवादियो ने मार्क्सवाद के विद्यमान स्तर की पूजा-अर्चना ही की । इससे समय के साथ पूंजीवादी

(शेष पेज 2 पर)

हमारे लक्ष्य हैं:— 1. मौजूदा व्यवस्था को बदलने के लिये इसे समझने की कोशिशें करना और प्राप्त समझ को ज्यादा से ज्यादा मजदूरों तक पहुंचाने के प्रयास करना । 2. पूंजीवाद को दफनाने के लिए जरूरी दुनियां के मजदूरों की एकता के लिये काम करना और इसके लिये आवश्यक विश्व कम्युनिस्ट पार्टी बनाने के काम में हाथ बटाना । 3. भारत में मजदूरों का क्रान्तिकारी संगठन बनाने के लिये काम करना । 4. फरीदाबाद में मजदूर पक्ष को उभारने के लिये काम करना ।

समझ, संगठन और सघर्ष की राह पर मजदूर आन्दोलन को आगे बढ़ाने के इच्छुक लोगों को ताल-मेल के लिये हमारा खुला निमन्त्रण है । बातचीत के लिये बेझिझक मिलें । टीका टिप्पणी का स्वागत है—सब पत्रों के उत्तर देने के हम प्रयास करेंगे ।

संपर्क—मजदूर लाइब्रेरी, आटोपिन झुग्गी, बाटा चौक के पास, एन. आई. टी. फरीदाबाद 121001

मार्क्सवाद

तीसरी किश्त

मजदूर वर्ग का क्रान्तिकारी सिद्धान्त पूंजीवाद के क्रान्तिकारी उन्मूलन के लिये उसे भौतिकवादी नजरिये से समझने की कोशिश करता है। आइये इस अंक से मार्क्सवाद के इस बुनियादी उसूल पर चर्चा आरम्भ करें।

जीवित मानव ही मानव समाज का गठन कर सकते हैं। रोटी और सुरक्षा जीवन की मूलभूत आवश्यकतायें हैं। अतः जब तक जीवन की इस बुनियादी आवश्यकताओं की कमी रहती है तब तक मानवों को, मानव समाज को इनकी प्राप्ति पर सर्वप्रथम और सर्वोपरि ध्यान केन्द्रित करना आवश्यक होता है। अपनी इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति मानव किस प्रकार करते हैं यह उनकी मर्जी पर निर्भर नहीं करता बल्कि यह उपलब्ध साधनों पर निर्भर करता है। और उपलब्ध साधन हैं कि बदलते रहते हैं— मानव इन्हें बदलने के कार्य में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। यहां यह अच्छी तरह समझने की जरूरत है कि व्यक्ति अथवा समाज का कोई अन्य मसला किसी समय कितना ही महत्वपूर्ण क्यों न हो अथवा लगता हो, व्यक्ति अथवा समाज के अस्तित्व में होने की स्थिति में ही तो उनका कोई अर्थ बनता है।

समाज की मार्क्सवादी भौतिकवादी व्याख्या इसे इस प्रकार रखती है: जीवन की भौतिक आवश्यकताओं की जब तक तंगी रहती है तब तक इन भौतिक जरूरतों की प्राप्ति की प्रक्रिया सामाजिक जीवन को अन्ततः निर्धारित करती है।

इस मार्क्सवादी प्रस्थापना की पहली बात तो यह है कि यह तंगी वाली समाज व्यवस्थाओं के नियमों की ही चर्चा कर रही है। समाज में जब तक रोटी और सुरक्षा की कमी वाले हालात रहेंगे तब तक ही जीवन की भौतिक आवश्यकताओं का उत्पादन सामाजिक जीवन को अन्तिम विश्लेषण में निर्धारित करेगा। बहुतायत वाले समाज में —अपनी उत्पादक क्षमता विकसित करके ऐसी साम्यवादी समाज के मुहाने आज हम खड़े हैं— ऐसे समाज की सामाजिक प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले नियमों की बात मार्क्सवाद नहीं करता। स्पष्ट कर दें, मार्क्सवाद निश्चित सामाजिक परिस्थितियों में निश्चित सामाजिक प्रक्रिया के नियमों की बात करता है— सार्विक नियमों (यूनिवर्सल लॉज) से मार्क्सवाद का कोई लेना-देना नहीं है। वास्तव में, मार्क्सवाद को सार्विक बना कर देव-प्रतिष्ठा प्रदान करना समाजवाद का नकाब लगाये राज्य-पूंजीवाद के अनुकूल मार्क्सवाद को विकृत करना रहा है और चूंकि राज्य-पूंजीवादी स्वयं को मार्क्सवादी प्रचारित करते रहे हैं इसलिए वे मार्क्सवाद के मजदूर वर्ग का क्रान्तिकारी सिद्धान्त होने की बजाय मार्क्सवाद को विज्ञान, साइन्स "सिद्ध" करने में काफी खर्च करते रहे हैं। मार्क्सवाद न तो सामाजिक विज्ञान है और न ही यह कोई सार्विक विज्ञान है बल्कि यह तो पूंजीवाद के क्रान्तिकारी उन्मूलन के लिये उसे समझने के लिये उसकी भौतिकवादी व्याख्या करता है। भौतिकवादी व्याख्या इस काम में सक्षम है—इस निष्कर्ष पर मार्क्सवाद विगत व वर्तमान के सामाजिक सगठनों के अध्ययन के पश्चात पहुँचा है। इस बारे में अधिक चर्चा हम अगले अंकों में करेंगे।

इस मार्क्सवादी प्रस्थापना की दूसरी बात यह है कि जीवन की भौतिक आवश्यकताओं का उत्पादन अन्ततः यानि अन्तिम विश्लेषण में ही सामाजिक प्रक्रिया को निर्धारित करता है। हर मामले को भौतिक उत्पादन से जोड़ने के बचकाना प्रयासों से मार्क्सवाद का कोई लेना-देना नहीं है। अतः जीवन का भौतिक उत्पादन प्रत्यक्ष तौर पर जिन्हें प्रभावित करता नहीं लगता ऐसे मामले इधर-उधर से चुनकर मार्क्सवाद के खण्डन के ढोल बजाने वाले अपनी अज्ञानता अथवा कुटिलता का ही प्रदर्शन करते हैं।

अगले अंक में इस चर्चा को जारी रखते हुए हम यह स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे कि अन्ततः यानि अन्तिम विश्लेषण में सामाजिक जीवन का भौतिक उत्पादन किस प्रकार अब तक के सामाजिक संगठनों की जीवन-क्रिया को निर्धारित करता रहा है।

(जारी)

——प्रो

—o—

ईस्ट इंडिया कॉटन

800 न्यूनतम वेतन वाली हरियाणा सरकार की घोषणा को 15 महीने हो गये हैं पर फरीदाबाद की अधिकतर फैक्ट्रियों में यह अभी तक लागू नहीं हुआ है। जिन बड़ी फैक्ट्रियों में परमानेन्ट मजदूरों के मामले में इसे लागू किया गया है वहां भी मैनेजमेंटें किस्म-किस्म की हेरा-फेरियां कर रही हैं। मैनेजमेंटों की ऐसी ही एक हेरा-फेरी के खिलाफ ईस्ट इन्डिया काटन (पावरलूम) के मजदूरों ने सांझा कदम उठाया है। हरियाणा सरकार के गजट के मुताबिक दो लूम ड्राबक्स के वर्कर उच्च कुशलता प्राप्त श्रमिकों के ग्रेड में हैं। गजट के अनुसार ऐसे मजदूरों का न्यूनतम वेतन 975 रुपए होना चाहिए पर ईस्ट इन्डिया मैनेजमेंट इन मजदूरों को 910 के रेट से पेमेन्ट कर रही है। मजदूरों ने अलग-अलग से यह मामला बार-बार मैनेजमेन्ट को स्पष्ट किया पर मैनेजमेन्ट ने उनकी बात पर कोई गौर नहीं किया। इस पर दो लूम ड्राबक्स के मजदूरों ने सामूहिक तौर पर अपनी बात मैनेजमेन्ट के सम्मुख रखने के लिए कदम उठाया। ईस्ट इन्डिया के इस प्रकार के समस्त मजदूरों के हस्ताक्षरों वाले पत्र से मैनेजमेन्ट में हलचल मची हुई है।

—x—

फरीदाबाद में कर्फ्यू

27 सितम्बर को अचानक दोपहर में फरीदाबाद में कर्फ्यू लगा दिया गया— 2 अक्टूबर को छपने के लिए यह सामग्री देते समय भी कर्फ्यू जारी था। सड़क पर नागरिकों को देखते ही गोली मारने की घोषणायें सरकार लाउडस्पीकर पर करती रही। हथियारों से लेस फौजियों ने अपनी गाड़ियों में बैठ कर गश्त लगाई। इस औद्योगिक क्षेत्र की विशाल मजदूर आबादी की आरक्षण—वारक्षण के झमेले में कोई रुचि नहीं थी इसलिए मोटे तौर पर फरीदाबाद में विशेष तनाव जैसी कोई चीज तक नहीं थी। इसलिए जनता दल की उठा-पटक में शतरंज की एक चाल के तौर पर ही इस कर्फ्यू को समझा जा सकता है। कई छुट्टियों वाले इस वक्त पर मैनेजमेन्टों को कर्फ्यू से नुकसान के बजाय लाभ ही था इसलिए उन्होंने कर्फ्यू का विरोध करने की बजाय चुपचाप मुस्करा कर तमाशा देखा। फरीदाबाद-बल्लभगढ़ औद्योगिक कम्पलैक्स में यह कर्फ्यू लगाना, देखते ही गोली मारने की घोषणायें और फौज की गश्त मजाक ही थे। पर मजदूरों के लिये यह एक तकलीफ दायक मजाक था। क्योंकि उनका वेतन कटेगा, दस रुपये किलो प्याज हो गये, छुट्टियां बरबाद हुई और पुलिस के डन्डे बोनस में पाये।

—o—

(पहले पेज का शेष)

सांचे में ढलते गए मार्क्सवादी जहां "आधिकारिक" मार्क्सवादी बनते गये वहीं मार्क्सवाद के मूल, मुक्ति-लक्ष्य को अपनाये रहे मार्क्सवादी छुट-पुट पंथों में सठिया गये। और पूंजीवादी सांचे में ढले "आधिकारिक" मार्क्स-वादियों ने द्वितीय व फिर तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय की प्रतिष्ठा का प्रयोग अपनी-अपनी पूंजीवादी वास्तविकता पर पर्दा डालने के लिए किया। इन परिस्थितियों में पूंजीवादी व्यवस्था के गहराते संकट के साथ बढ़ते सामा-जिक असन्तोष की अभिव्यक्ति के लिए दो प्रमुख सम्भावनायें बनीं—

1. राज्य-पूंजीवाद की सचालक क्रूर फौजी-नौकरशाही मशीनरी और
2. राज्य-पूंजीवाद को राक्षस निरूपित करने वाली विभिन्न रंग-रूप वाली क्रूर फौजी नौकरशाही मशीनरियां। विगत में कम्युनिस्ट आन्दोलन की मजदूरों व अन्य मेहनतकशों में प्रतिष्ठा की वजह से कम्युनिस्ट का नकाब लगाये राज्य-पूंजीवाद को दुनिया-भर में बढ़ते सामाजिक असन्तोष ने तब तक अपना आदर्श स्वीकार किया जब तक कि राज्य-पूंजीवाद की हकीकत बड़े पैमाने पर सामने नहीं आई। चीन-उत्तरी कोरिया-वियतनाम कम्बोडिया-क्यूबा जैसे कई इलाकों में इनकी परिणति क्रूर फौजी-नौकर-शाही मशीनरियों की स्थापना में हुई। कहा जा सकता है कि स्तालिन की मृत्यु तक आमतौर पर दुनिया के अधिकतर हिस्सों का सामाजिक असन्तोष राज्य-पूंजीवाद को आदर्श मानता था व बाद में भी माओवादी रूप में राज्य-पूंजीवाद कुछ समय तक आकर्षक रहा। पर आज रूस-चीन-पूर्वी यूरोप में राज्य-पूंजीवाद के दिवालिएपन का भांडा बीच चौराहे पर फूट जाने के बाद सामाजिक असन्तोष स्वयं को विभिन्न रंग रूप वाली क्रूर फौजी-नौकरशाहियों में अभिव्यक्त कर रहा है। इस प्रकार क्रान्ति-कारी मजदूर आन्दोलन के सचेत विकाश के लिए आवश्यक मार्क्सवाद का विकाश न होने की स्थिति में पूंजीवादी व्यवस्था में बढ़ता सामाजिक असन्तोष अपने को इस या उस मानवघाती पूंजीवादी धारा में अभिव्यक्त कर रहा है। सबक है: क्रान्तिकारी मजदूर आन्दोलन के सचेत विकाश के लिए मार्क्सवाद का विकास जरूरी है।

—o—

स्वत्वाधिकारी व सम्पादक शेरसिंह द्वारा आटोपिन झुग्गी, फरीदाबाद से प्रकाशित व अलकनन्दा प्रिंटिंग प्रेस C-III/206, सं. गां. मेमो. न. से मुद्रित